

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 01 SEPTEMBER TO 07 SEPTEMBER 2021



■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 07 ■ अंक 1 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

स्वास्थ्य व पर्यावरण के मोर्चे पर बड़ी सफलता सीसा-युक्त पेट्रोल के इस्तेमाल पर रोक



Page 2

Page 3



Page 5

ऑल -न्यू रॉयल एनफाइल क्लासिक 350 लीजेंड का हुआ पुर्नजन्म



editoria!

तीव्र वृद्धि दर

चालू वित वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि दर 18.5 प्रतिशत के आसपास रह सकती है। भारतीय स्टेट बैंक की शोध रिपोर्ट में यह अनुमान लगाते हुए कहा गया है कि चार हजार से अधिक कंपनियों ने इस अवधि में 28.4 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की है। चूंकि यह बीते वित वर्ष की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च, 2021) से कम है, इसलिए स्टेट बैंक का आकलन भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान 21.4 प्रतिशत से कम है। लेकिन इस महत्वपूर्ण तथ्य का संज्ञान लिया जाना चाहिए कि अप्रैल से जून के बीच ही भारत को कोरोना महामारी की भयावह दूसरी लहर का सामना करना पड़ा था और ऐसा लगने लगा था कि अर्थव्यवस्था पिछले वित वर्ष की दो तिमाहियों की तरह मंदी की चेपेट में आ सकती है। यह वृद्धि दर न केवल संतोषजनक है, बल्कि आगे के लिए भी उत्साहवर्धक है। महामारी की पहली लहर के अनुभवों से सीख लेते हुए केंद्र और राज्य सरकारों ने दूसरी लहर में समझदारी के साथ पार्दियों को लागू किया था। उद्योग और कारोबार जगत ने भी आर्थिक गतिविधियों को कमोबेश जारी रखा। इसके परिणामस्वरूप पहली तिमाही में अपेक्षा से कहीं अधिक राजस्व संग्रहण हुआ, जो पिछले पांच वर्षों में सर्वाधिक है। अप्रैल से जून के बीच बजट के सालाना लक्ष्य के 28 प्रतिशत राजस्व की वसूली की उम्मीद है। निश्चित रूप से यह व्यक्तिगत और कॉरपोरेट कमाई में बढ़त का सूचक है। उल्लेखनीय है कि महामारी के पहले के तीन वर्षों में पहली तिमाही में बजट लक्ष्य का 14 प्रतिशत राजस्व सरकार के पास आ पाता था। अर्थव्यवस्था के प्रमुख इंफास्ट्रक्चर क्षेत्रों में भी बढ़ोतरी हो रही है। उड़ान सेवाओं में भी अच्छी वृद्धि के संकेत हैं। बाजारों और मनोरंजन से जुड़ी जगहों में भी पार्दियों में ढील के साथ लोगों का आना-जाना बढ़ रहा है। इन कारकों से इंगित होता है कि अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे ही सही, पर सधे कदमों से बढ़ोतरी की ओर अग्रसर है। पिछले साल भारी गिरावट से प्रस्त आर्थिक गतिविधियों को संभालने और उन्हें आगे ले जाने के लिए सरकार ने लगातार राहत पैकेजों की घोषणा की थी तथा लोगों एवं व्यवसायों को कर्ज देने व पूंजी जुटाने में सहृदयता दी गयी थी। गरीबों और निम्न आयवर्ग के कल्याण की विशेष योजनाएं अभी भी जारी हैं। इसके अलावा, महामारी की रोकथाम के अन्य उपायों तथा तीसरी लहर को रोकने के प्रयासों के साथ टीकाकरण अभियान भी जारी है। इन सब पहलों ने अर्थव्यवस्था के प्रति भरोसा बहाल करने तथा विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए बड़ा आधार मुहूर्या कराया है। अब यह भी उम्मीद की जा सकती है कि आर्थिक वृद्धि से घरेलू मांग भी तेजी से बढ़ेगी तथा निर्यात भी अधिक हो सकेगा। निवेशकों का भी भरोसा बना हुआ है। ऐसे में एक-दो साल के भीतर अर्थव्यवस्था के महामारी के पहले की स्थिति में आने की संभावना बेहद मजबूत है।

इंडॉर एजेंसी

देश की अर्थव्यवस्था अब पटरी पर लैटेने लगी है। जीडीपी अंकड़ों में सुधार के बाद अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी कलेक्शन के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। दरअसल, जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन एक बार फिर 1 लाख करोड़ रुपए के स्तर को पार कर लिया है। अगस्त महीने में ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू 1,12,020 करोड़ रुपए रहा। एक साल पहले की इसी अवधि से तुलना करें तो जीएसटी राजस्व में 30 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, जुलाई 2021 के मुकाबले अगस्त में जीएसटी कलेक्शन कम हुआ है। जुलाई में कितना था कलेक्शन: जुलाई, 2021 में 1,16,393 करोड़ रुपए का ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन था। इसमें सीजीएसटी 22,197 करोड़ रुपए, एसजीएसटी 28,541 करोड़ रुपए, आईजीएसटी 57,864 करोड़ रुपए और उपकर

(सेस) 7,790 करोड़ रुपए शामिल हैं। आपको बता दें कि जीएसटी संग्रह लगातार आठ महीने तक



1 लाख करोड़ से अधिक रहने के बाद जून 2021 में घटकर 1 लाख करोड़ रुपए के स्तर से नीचे आ गया था। जून 2021 महीने के दौरान संग्रह काफी हद तक मई 2021 से संबंधित था। मई 2021 के दौरान अधिकतर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश कोविड

की दूसरी लहर के कारण पूर्ण अथवा आंशिक लॉकडाउन से जूझ रहे थे। कोविड संबंधी पार्दियों में ढील के साथ ही जुलाई और अगस्त 2021 के लिए जीएसटी संग्रह फिर से 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है। आने वाले महीनों में भी जीएसटी राजस्व संग्रह दमदार बने रहने की सभावना है। जीडीपी के मोर्चे पर भी अच्छी खबर: कोरोना वायरस की खतरनाक दूसरी लहर के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था में चालू वित वर्ष की पहली तिमाही में 20.1 प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई। इसका कारण पिछले वित वर्ष की पहली तिमाही का तुलनात्मक आधार नीचे होना है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर का बेहतर प्रदर्शन भी जीडीपी ग्रोथ का कारण है।

आर्थिक आंकड़ों से बाजार गदगद, सेंसेक्स-निपटी को मिली नई ऊंचाई

इंडॉर एजेंसी

मंगलवार का दिन अच्छा रहा। जहां कोरोना वायरस की खतरनाक दूसरी लहर के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था में चालू वित वर्ष की पहली तिमाही में 20.1 प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई, वहीं बुनियादी ढांचा क्षेत्र के आठ उद्योगों का उत्पादन जुलाई में 9.4 प्रतिशत बढ़ा है। शेयर बाजार में भी रैनक: इसके अलावा घरेलू शेयर बाजारों में जोरदार तेजी का सिलसिला जारी रहा। मंगलवार को बीएसई सेंसेक्स 663 अंक उछलकर पहली बार 57,000 अंक के ऊपर नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। एनएसई निपटी भी 17,000 अंक के ऊपर निकल गया। बाजार में तेजी के साथ बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण उछलकर अब तक वे उच्चतम स्तर 2,50,02,084.01 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। सेंसेक्स को 56,000 से 57,000 अंक के बंद स्तर पर पहुंचने में केवल दो दिन लगे।

मंगलवार का दिन अच्छा रहा। जहां कोरोना वायरस की खतरनाक दूसरी लहर के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था में चालू वित वर्ष की पहली तिमाही में 20.1 प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई, वहीं बुनियादी ढांचा क्षेत्र के आठ उद्योगों का उत्पादन जुलाई में 9.4 प्रतिशत बढ़ा है। शेयर बाजार में भी रैनक: इसके अलावा घरेलू शेयर बाजारों में जोरदार तेजी का सिलसिला जारी रहा। मंगलवार को बीएसई सेंसेक्स 663 अंक उछलकर पहली बार 57,000 अंक के ऊपर नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। एनएसई निपटी भी 17,000 अंक के ऊपर निकल गया। बाजार में तेजी के साथ बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण उछलकर अब तक वे उच्चतम स्तर 2,50,02,084.01 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। सेंसेक्स को 56,000 से 57,000 अंक के बंद स्तर पर पहुंचने में केवल दो दिन लगे।

मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस: भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत

नई दिल्ली। एजेंसी

मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 31 अगस्त को कहा कि भारत में आर्थिक गतिविधियां धीरे-धीरे ठीक हो रही हैं क्योंकि एचडब्ल्यूपी ग्रेड ग्रेड धीरे-धीरे कम हो रहे हैं। मूडीज ने कहा, 'भारत में, दूसरी लहर के जवाब में लागू किए गए प्रतिबंधों में धीरे-धीरे ढील के साथ आर्थिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। और दूनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के उत्तरोत्तर फिर से खुलने से विकास में और तेजी आई है।' मूडीज ने अपने 'ग्लोबल

शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया पांच पैसे दूटा मुबई। एजेंसी

भारतीय रुपया बुधवार के शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पांच पैसे फिसलकर 73.05 पर आ गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि हालांकि मजबूत व्यापक आर्थिक आंकड़ों और घरेलू शेयर बाजार में तेजी ने रुपये की गिरावट को थामने का काम किया। अंतर्राष्ट्रीय विदेशी मुद्रा विनियम बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 73.05 पर खुला, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले पांच पैसे की गिरावट दर्शाता है। रुपया पिछले स्तर में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 73.00 पर बंद हुआ। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.12 प्रतिशत बढ़कर

स्वास्थ्य व पर्यावरण के मोर्चे पर बड़ी सफलता

सीसा-युक्त पेट्रोल के इस्तेमाल पर रोक

एजेंसी

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एजेंसी (लॉन्डिंग) के नेतृत्व में स्वच्छ ईंधन व वाहनों के लिये, दो दशकों से जारी प्रयासों के परिणामस्वरूप, वैश्विक स्तर पर सीसा-युक्त पेट्रोल के इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से विराम लग गया है। इस वर्ष जुलाई महीने में अल्जीरिया के सर्विस स्टेशनों पर सीसा-युक्त पेट्रोल की बिक्री बन्द कर दी गई।

इसके साथ ही आधिकारिक रूप से दुनिया भर में सीसा-युक्त पेट्रोल के इस्तेमाल पर अब पूरी तरह पाबन्दी लग गई है। यूएन पर्यावरण एजेंसी की कार्यकारी निदेशक इनार एण्डरसन ने बताया कि वैश्विक स्वास्थ्य और हमारे पर्यावरण के लिये सीसा-युक्त पेट्रोल पर पाबन्दी को सफलतापूर्वक लागू किया जाना एक बेहद अहम पड़ाव है। वर्ष 1922 से, इन्जन के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिये टेट्राएथिलेन को पेट्रोल में मिलाया जाता रहा है। मगर, इस वजह से कई दशकों तक वायु, धूल, मृदा,

पेयजल और फसलें दूषण का शिकार हुई और यह मानव स्वास्थ्य के लिये भी समस्या बन गया। वर्ष 1970 तक दुनिया भर में लगभग हर जगह पेट्रोल के उत्पादन में सीसे का इस्तेमाल किया जाता था।

पर्यावरण व स्वास्थ्य के लिये खत्रा

वर्ष 2002 में जब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एजेंसी ने पेट्रोल में सीसे के इस्तेमाल के उन्मूलन के लिये अपनी मुहिम शुरू की, तो यह मानव स्वास्थ्य के लिये सबसे गम्भीर खतरों में था। सीसा-युक्त पेट्रोल से हृदय रोग, स्ट्रोक और कैन्सर जैसी बीमारियाँ होने का जोखिम होता है और मानव स्थिति के विकास पर भी असर पड़ता है। बच्चों के लिये यह विशेष रूप से नुकसानदेह है। लाखों-करोड़ों को प्रभावित करने वाली, पर्यावरण के क्षण और एक सदी से हो रही मौतों व बीमारियों के लिये ज़िम्मेदार बजहों पर मिली इस कामयाबी से स्वच्छ वाहनों और बिजली चालित वाहनों की दिशा में तेज़ी से आगे



बढ़ने में मदद मिलेगी।

बताया गया है कि सीसा-युक्त पेट्रोल के इस्तेमाल पर पाबन्दी से प्रति वर्ष 12 लाख असामिक मौतों को टालना सम्भव हो सकेगा। बच्चों के लिये आईक्यू प्वाइंट्स में इज़ाफ़ा होगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिये दो हजार 450 अरब डॉलर की बचत होगी।

चुनौती बरकरार

हालांकि इस प्रगति के बावजूद, वैश्विक वाहनों का तेज़ी से बढ़ता बेड़ा, स्थानीय स्तर पर वायु, जल व मिट्टी के प्रदूषण के लिये ज़िम्मेदार है। साथ ही वैश्विक जलवायु संकट भी बढ़ता है। एक अनुमान के

मुताबिक, ऊर्जा-सम्बन्धी वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्पर्जनों में परिवहन सैक्टर का कृती एक-चौथाई योगदान है। वर्ष 2050 तक यह आँकड़ा बढ़कर एक तिहाई हो जाने की आशंका है। अनेक देशों ने बिजली-चालित वाहनों की दिशा में कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है, मगर आने वाले सालों में एक अरब 20 करोड़ वाहन सड़कों पर उतरेंगे। इनमें खराब गुणवत्ता वाले और पहले इस्तेमाल में लाए जा चुके वो लाखों वाहन भी हैं जिनका योरोपीय देशों, अमेरिका और जापन से मध्य और निम्न आय वाले देशों को निर्यात किया जाता है। इनके

इस्तेमाल से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, वायु प्रदूषित करने वाला ट्रैफ़िक होता है और दुर्घटना की आशंका भी बढ़ जाती है।

हरित भविष्य की ओर

यूएन पर्यावरण एजेंसी की प्रमुख इनार एण्डरसन ने कहा कि सरकारों, व्यवसायों और नागरिक समाज के संयुक्त राष्ट्र-समर्थित एक गठबन्धन के ज़रिये दुनिया को इस ज़हरीले ईंधन से निजात दिलाने में सफलता मिली है। उनके मुताबिक यह विश्व को एक स्वच्छ व हरित भविष्य की दिशा में ले जाने में बहुपक्षवाद की शक्ति को दर्शाता है। 'हम इर्ही प्लॉक्करों से इस विशाल उपलब्धि से प्रेरणा लेने का आग्रह करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके, कि हमारे पास स्वच्छतर ईंधन होने के बाद, हम पहले से स्वच्छ वाहनों के वैश्विक मानकों को भी अपना सकें। स्वच्छतर ईंधन और वाहनों के ज़रिये उत्पर्जनों में 80 फ़ीसदी की कटौती लाई जा सकती है।'

यूएन एजेंसी की आगाह किया है कि सीसा प्रदूषण के सबसे बड़े स्रोत के उन्मूलन में सफलता ज़रूर मिली है, मगर अन्य स्रोतों से होने वाले सीसा प्रदूषण पर विराम लगाने के लिये कार्रवाई की आवश्यकता है।

इनमें पेण्ट में इस्तेमाल होने वाली सीसा, सीसे का प्रयोग करने वाली बैटरी और घर-गृहस्थी के सामान में इस्तेमाल होने वाला सीसा है। सीसा-युक्त पेट्रोल के इस्तेमाल के अन्त से टिकाऊ विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति में मदद मिलने की उम्मीद है। इनमें अच्छे स्वास्थ्य व कल्याण (एसडीजी-3), स्वच्छ जल (एसडीजी-6), स्वच्छ ऊर्जा (एसडीजी-7), टिकाऊ शहर (एसडीजी-11), जलवायु कार्रवाई (एसडीजी-13) और भूमि पर जीवन (एसडीजी-15) लक्ष्य शामिल हैं। साथ ही, इस वर्ष 7 सितम्बर को, 'नीले आकाश के लिये स्वच्छ वायु के अन्तरराष्ट्रीय दिवस' से पहले यह ठोस प्रगति को भी दर्शाता है।

ओएनजीसी अपतटीय क्षेत्रों में पवन ऊर्जा परियोजनाएं लगाने पर कर रही विचार

नयी दिल्ली। एजेंसी

देश की सबसे बड़ी तेल एवं गैस उत्पादक कंपनी ओएनजीसी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अपनी क्षमता बढ़ाने के इरादे से अपने व्यापक अपतटीय क्षेत्रों में पवन ऊर्जा परियोजनाएं लगाकर बिजली उत्पादन करने पर विचार कर रही है। कंपनी के चेयरमैन सुभाष कुमार ने यह कहा। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) के पास अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों जगहों पर तेल एवं गैस फील्ड हैं। कंपनी छिल्ले और गहरे सागर में काम करने के अनुभव का उपयोग अब पवन ऊर्जा परियोजनाएं लगाने में करने पर विचार कर रही है। इन परियोजनाओं से उत्पादित बिजली का दूसरी जगहों पर उपयोग के लिये पर्याप्त किया जाएगा।

कुमार ने कंपनी की सालाना रिपोर्ट में कहा, "अपतटीय पवन ऊर्जा के लिये पायलट परियोजना को लेकर अध्ययन शुरू किया गया है। इसका मकसद इस खंड में अवसरों का आकलन करना है।" उल्लेखनीय है कि पिछले साल ओएनजीसी ने 7,600 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा पर पवन ऊर्जा परियोजनाएं लगाने की संभावना टटोलने को लेकर देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी के साथ समझौता ज्ञापन

पर हस्ताक्षर किये थे।

अपतटीय पवन चक्रिकायां तटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की तुलना में लगभग दोगुनी कुशल होती है। लेकिन समुद्री वातावरण में आवश्यक मजबूत संचनाओं और नींव के कारण अपतटीय टर्बाइन के लिए प्रति मेगावाट लागत अधिक है। सरकार ने 2022 तक अपतटीय क्षेत्रों में 5,000 मेगावाट तथा 2030 तक 30,000 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजनाएं लगाने का लक्ष्य रखा है। यानी हमें इस क्षेत्र में लंबा रास्ता तय करना है।

सिपेट की कार्यशाला में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर जोर लखनऊ। एजेंसी

सिपेट लखनऊ में एआईसीटीई नई दिल्ली की अटल एकेडमी द्वारा प्रायोजित एक पांच दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित किया गया। कार्यशाला में देश के विभिन्न राज्यों के 100 से अधिक प्रौद्योगिकी संस्थानों के शिक्षकों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में उद्योग जगत के विशेषज्ञों और कई वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े अलग-अलग विषयों पर अपने अनुभव एवं ज्ञान को साझा किया। कार्यशाला के समाप्त समारोह में संस्था के प्रधान निदेशक एवं प्रमुख प्रोफेसर आरएम मिश्रा ने इस अत्यन्त गम्भीर समस्या में चिन्तन की आवश्यकता है। सिपेट वराणसी के प्रधान निदेशक एवं प्रमुख डा. एसएन यादव ने भी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को समय की सबसे आवश्यक जरूरत बताते हुए आयोजकों को बधाई दी।

नई दिल्ली। एजेंसी

देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ सोलर एनर्जी में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक रिलायंस सोलर पैनल बनाने वाली यूरोप की सबसे बड़ी कंपनी आईसीपी ग्रुप को खरिदने के बेहद कठिन है। इसके लिए रिलायंस की चाइना नेशनल केमिकल कॉर्प से बातचीत चल रही है। यह डील 1 से 1.2 अरब डॉलर में हो सकती है।

इससे मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस की पहुंच आधुनिक टेक्नोलॉजी और ग्लोबल कैम्पियरिंग क्षमताओं तक हो जाएगी। कंपनी ने हाल में ग्रीन एनर्जी सेक्टर में उत्तराने की घोषणा की थी। सूत्रों के मुताबिक इस सोलर पैनल बनाने के लिए 50 से 60 करोड़ डॉलर जुटाने के लिए ग्लोबल बैंक्स से बात कर रही है। बाकी राशि इक्विटी के जरिए जुटाई जाएगी। आईसीपी ग्रुप का हेडक्वार्टर नॉर्थ में है जबकि यह सिंगापुर में रजिस्टर्ड है।

चीन पर निर्भरता होगी कम

आईसीपी ग्रुप चीन की सरकारी केमिकल कंपनी केमचाइना की इंटरनेशनल मेंबर है। एप्पसर्प्हर्न की इगल्ट ऊब्री और एब्हुर्ह में सबसे अधिक हिस्सेदारी है। आईसीपी

फोटोवॉल्टेइ

सरकार ने विभिन्न कर अनुपालनों, जीएसटी राहत के लिए समयसीमा बढ़ाई

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

आयकर विभाग ने रविवार को सामान्यीकरण शुल्क (इक्वलाइजेशन लेवी) एवं प्रेषण (रेमिटेंस) के लिए विवरण दाखिल करने से जुड़े विभिन्न अनुपालनों और जीएसटी माफी योजना का लाभ उठाने की समयसीमा बढ़ा दी। सरकार ने सामान्यीकरण शुल्क (इक्वलाइजेशन लेवी) एवं प्रेषण (रेमिटेंस) के लिए विवरण दाखिल करने के संबंध में, करदाताओं की इस तरह के फॉर्म को भरने में होने वाली दिवकरों से पार पाने में मदद करने के लिए यह कदम उठाया है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म-1 में सामान्यीकरण शुल्क व्योरा दाखिल करने की समयसीमा 30 जून की मूल नियत तारीख के मुकाबले 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गयी है।

जून और सितंबर तिमाही के लिए गए

प्रेषण के संबंध में अधिकृत डीलों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले फॉर्म 15सीसी में ट्रैमासिक विवरण अब क्रमशः 30 नवंबर और 31 दिसंबर तक दायर किया जा सकता है। इस विवरण को दाखिल करने की मूल नियत तारीख क्रमशः 15 जुलाई और 15 अक्टूबर थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा कि करदाताओं और अन्य हितधारकों द्वारा कुछ फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दाखिल करने में आ रही दिवकरों की जानकारी दी गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए इन फॉर्म की ई तरीके से जमा करने की तारीखों को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है।

एक अलग बयान में, सीबीडीटी ने प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना 'विवाद से विश्वास' (वीएसटी) के तहत भुगतान करने की समयसीमा 30 सितंबर

तक एक महीने तक बढ़ाने की घोषणा की। हालांकि करदाताओं के पास अतिरिक्त व्याज राशि के साथ 31 अक्टूबर तक भुगतान करने का विकल्प होगा। सरकार ने यह कदम कोविड-19 महामारी के समय में करदाताओं की मदद करने के लिए उठाया है।

इसके अलावा जीएसटी माफ करने की योजना का लाभ उठाने की अंतिम तारीख तीन महीने के लिए बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गयी है। योजना के तहत करदाताओं को मासिक रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए कम शुल्क का भुगतान करना होगा। वहीं जीएसटी रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (ईवीसी) दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गयी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने मई में लंबित रिटर्न के लिए करदाताओं को विलंब

शुल्क में राहत प्रदान करने की खातिर एक माफी योजना लाने का फैसला किया था। सभी राज्यों के वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के सदस्य हैं।

जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 के लिए जीएसटीआर-3बी दाखिल ना करने पर उन करदाताओं की खातिर विलंब शुल्क 500 रुपये प्रति रिटर्न तक सीमित कर दिया गया है, जिन पर कोई कर देयता नहीं है। वहीं कर देयता वाले लोगों के लिए, अधिकतम 1,000 रुपये प्रति रिटर्न विलंब शुल्क लिया जाएगा, बशर्ते ऐसे रिटर्न 31 अगस्त, 2021 तक दाखिल कर दिए गए हों। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'विलंब शुल्क माफी योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि अब मौजूदा 31 अगस्त, 2021 से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2021 कर दी गयी है।'

उलझन: गोल पापड़ पर जीएसटी नहीं, चौकोर पर लगेगा

ट्वीट पर अब सीबीआईसी ने दिया ये जवाब

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

उद्योगपति हर्ष गोयनका के 'गोल पापड़ जीएसटी मुक्त है और चौकोर पापड़ नहीं' वाले ट्वीट पर अब कर निकाय सीबीआईसी ने सफाई दी है। सीबीआईसी ने गोयनका के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि पापड़ किसी भी आकार का हो उसे जीएसटी से मुक्त रखा गया है। यह नोटिफिकेशन हमारे वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

जानिए क्या है मामला

दरअसल, उद्योगपति हर्ष गोयनका ने मंगलवार को एक ट्वीट कर कहा था कि, 'क्या आप जानते हैं कि गोल पापड़ को जीएसटी से मुक्त रखा गया है, जबकि चौकोर पापड़ पर जीएसटी लगता है?' क्या कोई किसी अच्छे चार्टर्ड एकाउंटेंट का नाम सुझा सकता है जिससे मैं इसका तर्क समझ सकूँ? सीबीआईसी (CBIC) ने दिया ये जवाब

हर्ष गोयनका के ट्वीट पर जवाब देते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) ने कहा कि 'पापड़ चाहे किसी भी आकार में क्यों न हो उसे नोटिफिकेशन संख्या 2/2017-CT(R) के तहत जीएसटी से मुक्त रखा गया है।' यह नोटिफिकेशन हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

गुजरात अर्थोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग्स ने भी सुनाया था फैसला

गौरतलब है कि कुछ महीने पहले ही गुजरात के अर्थोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग्स (GAAR) ने भी अपने एक आदेश में यह साफ किया था कि पापड़ चाहे किसी भी आकार और रूप में हो, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा।



लस्सी पर भी था जीएसटी विवाद

इसके अलावा लस्सी के मामले में भी गुजरात की एडवांस रूलिंग अर्थोरिटी (एएआर) ने फैसला सुनाया था कि लस्सी पर माल और सेवा कर (उएक्यु) नहीं लगेगा। लेकिन फ्लेवर्ड मिल्क पर ग्राहकों से 12 फीसदी का टैक्स वसूला जाएगा। दरअसल वलसाड स्थित निर्माता और आपूर्तिकर्ता संपूर्ण डेवरी एंड एंट्रोटेक ने लस्सी पर लागू जीएसटी की दर को लेकर एएआर-गुजरात से संपर्क किया था। अब कंपनी की दूध के उत्पादों पर लगने वाले टैक्स की कनफ्यूजन दूर हुई है।

जानिए क्या है जीएसटी

क्षमता एवं सेवा कर या जीएसटी को जुलाई 2017 में लागू किया गया था और इस व्यवस्था के तहत सभी केंद्रीय उत्पाद शुल्क और स्थानीय शुल्कों को समाहित कर दिया गया था। जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं की खपत आधारित कर है। गुदस एंड सर्विसेज टैक्स ने उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अधिभार और उपकर, विक्री कर, राज्य मूल्य वर्धित कर (वैट) और अन्य करों को एक ही कर से बदल दिया।

श्रीलंका को आईएमएफ से 78.7 करोड़ अमेरिकी डॉलर मिले

बांगलादेश से मुद्रा अदला-बदली कोलंबो। एजेंसी

श्रीलंका को आईएमएफ के विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) आवंटन से 78.7 करोड़ अमेरिकी डॉलर और बांगलादेश सेंट्रल बैंक से मुद्रा अदला-बदली समझौते के तहत 15 करोड़ अमेरिकी डॉलर मिले हैं,

जिससे उसके विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतारी होगी। गौरतलब है कि श्रीलंका कोरोना वायरस महामारी के चलते आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 23 अगस्त 2021 को सदस्य देशों के बीच उनके मौजूदा कोटा के अनुपात में 650 अरब अमेरिकी डॉलर के बाराबर कुल एसडीआर का आवंटन किया। सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका

ने मंगलवार को एक बयान में कहा,

"श्रीलंका को मिला एसडीआर आवंटन 78.7 करोड़ अमेरिकी डॉलर के बराबर है, जबकि बांगलादेशी बैंक के साथ मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था के तहत 15 करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि मिली।" बैंक ने कहा कि उसे जल्द ही चीन विकास बैंक से शेष सिंडिकेट कर्ज मिलने की उम्मीद है।

सूरत। एजेंसी

1 नवंबर से कंपनी द्वारा किए जानेवाले जीएसटी रिटर्न सहित सभी कार्य के लिए डिजिटल सिग्नेचर

के बजाय ओटीपी से भी कर सकेंगे ऐसा प्रावधान किया गया है। इसके कारण कंपनी संचालकों को बड़ी राहत मिली है। साझेदारी पेटी में या तो किसी भी कंपनी में जीएसटी रिटर्न भरने के लिए डिजिटल सिग्नेचर अनिवार्य का नियम लागू किया गया था। लेकिन

कोरोना के कारण केंद्र सरकार ने इसमें राहत देने का फैसला लेकर कंपनी संबंधित रिटर्न भरने के लिए ओटीपी से भी भरने की छूट दी गई थी।

लेकिन छूट केवल कोरोनाकाल तक ही सीमित रखने

रिटर्न भरने के लिए समय की राहत देखनी पड़ती है। इसके बजाय अब तकाल कार्यवाही कर सकेंगे। इसके कारण कंपनी संचालकों को दंड और व्याज भरने से भी मुक्ति मिलेगी।

प्लास्ट टाइम्स

व्यापार की बुलंद आवाज

अपनी प्रति आज ही बुक करवाएं

विज्ञापन के लिए संपर्क करें।

83052-99999

indianplasttimes@gmail.com

उम्मीद से बेहतर रहा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन

चीन काफी पीछे छूटा

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

भारतीय अर्थव्यवस्था ने कोरोना की दूसरी लहर से उबर कर उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) रिकॉर्ड 20.1 फीसदी की दर से बढ़ी। यह तमाम रिसर्च एंजेंसियों के लगाए गए अनुमान से बेहतर है। गौरतलब है कि कोरोना की पहली लहर के बाद पिछले साल समान तिमाही में जीडीपी की विकास दर -23.9 फीसदी रही थी।

चीन के मुकाबले

भारतीय अर्थव्यवस्था पहली तिमाही में दोगुने से अधिक रफ्तार से बढ़ी

चीन की वृद्धि दर 2021 की अप्रैल-जून तिमाही में 7.9 प्रतिशत रही है। यानी चीन के मुकाबले

देश में आने वाले हैं 2 नए बैंक, RBI को लाइसेंस के लिए दिया आवेदन

नई दिल्ली। एजेंसी

देश में दो नए बैंक आने वाले हैं। आने वाले समय में 2 नई कंपनियां स्मॉल फाइनेंस बैंक के तौर पर कार्य करेंगे। बैंक के तौर पर लाइसेंस के लिए दो फाइनेंशियल कंपनियों ने केंद्रीय बैंक आरबीआई (RBI) को आवेदन दिया है। रिजर्व बैंक की ओर से इन कंपनियों को लाइसेंस जारी करने के बाद ये कंपनियां बैंक के रूप में काम करने लगेंगी। आरबीआई की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, जिन दो फाइनेंशियल कंपनियों ने बैंक लाइसेंस के लिए आरबीआई के पास आवेदन किया है, उनमें कॉस्मिया फाइनेंशियल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड हैं।

कॉस्मिया फाइनेंशियल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड

24 नवंबर 2020 को शुरू की गई एक निजी कंपनी है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, मुंबई में कराए गए रजिस्ट्रेशन के अनुसार, इस कंपनी को गैर-सरकारी कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह कंपनी फिलहाल बीमा और पेंशन फंडिंग को छोड़कर वित्तीय मध्यस्थता के लिए सहायक गतिविधियों में शामिल है। सैमेन घोष और सुरेश तिरुवनंतपुरम विश्वनाथन कॉस्मिया फाइनेंशियल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं।

टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

8 नवंबर 1991 को शुरू की गई एक निजी कंपनी है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, बैंगलूरु में कराए गए पंजीकरण के अनुसार, इसे गैर-सरकारी कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह कंपनी मूलतः सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर गेम, बिजेनेस और अन्य एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंटेशन, वेब पेज डिजाइन वगैरह गतिविधियों में शामिल है। अब कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेस/बैंकिंग में अपना हाथ आजमाने जा रही है।

देश में पहले से संचालित हो रहे हैं कई प्राइवेट बैंक

एक्सिस बैंक	डीसीवी बैंक
बंधन बैंक	धनलक्ष्मी बैंक
एचडीएफसी बैंक	फेडरल बैंक
आईसीआईसीआई बैंक	आईडीएफसी बैंक
इंडसइंड बैंक	जम्मू एंड कश्मीर बैंक
यस बैंक	कर्नाटक बैंक
आईडीबीआई बैंक	करूर वैश्य बैंक
कोटक महिंद्रा बैंक	नैनीताल बैंक
लक्ष्मी विलास बैंक	आरबीएल बैंक
कैथोलिक सीरियन बैंक	साऊथ इंडियन बैंक
सिटी यूनियन बैंक	तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक

में चीनी अर्थव्यवस्था और सुस्त हो सकती है।

आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि जीडीपी की यह वृद्धि पिछले साल आई गहरी मंदी से बाहर निकलने का संकेत है। कोविड-19 की दूसरी खतरनाक लहर के बावजूद विनिर्माण में तेजी ने बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का तमागा हासिल कर ले गा। वहीं, चीन में मंगलवार को जारी एक सर्वेक्षण के मुताबिक नियर्त मांग कमजोर पड़ने से अगस्त में विनिर्माण गतिविधियां सुस्त पड़ीं। चीन के सांख्यिकी ब्यूरो और एक अधिकारिक उद्योग समूह द्वारा तैयार किया गया मासिक क्रय प्रबंधक सूचकांक जुलाई में 50.4 से घटकर अगस्त में 50.1 हो गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि चीन के नियर्त की मांग साल की दूसरी छमाही में कमजोर होने की आशंका है। इसके अलावा जुलाई में आई बाढ़ और कोरोना वायरस पर काबू पाने के उपायों के चलते भी विनिर्माण और उपभोक्ता गतिविधियां कम हुई हैं। यानी आने वाले समय

बेहतर तस्वीर के लिए हमें जीडीपी को तिमाही आधार पर देखना होगा। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान टोटल जीडीपी 30.1 लाख करोड़ रुपये का रहा। अगर सेक्टर के हिसाब से देखें, तो सबसे ज्यादा 6.8-3% का उठाल कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की सालाना ग्रोथ 49.6% रही, जबकि माइनिंग सेक्टर का ग्रोथ रेट 18.6% रहा। जून तिमाही में नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 31.7% रही, जबकि ग्रास वैल्यू ऐडेंड यानी जीवीए सालाना आधार पर 18.8% बढ़ा।

बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 9.4 प्रतिशत बढ़ा

बुनियादी क्षेत्र के आठ उद्योगों का उत्पादन जुलाई में 9.4 प्रतिशत बढ़ा है। मंगलवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। एक साल पहले इसी महीने में बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 7.6 प्रतिशत बढ़ा था। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के आंकड़ों के अनुसार जुलाई में

कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादों, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली क्षेत्र का उत्पादन एक साल पहले के इसी महीने की तुलना में बढ़ा है। हालांकि, इस दौरान कच्चे तेल के उत्पादन में 3.2 प्रतिशत की गिरावट आई। जुलाई, 2020 में कोविड-19 की वजह से लागू अंकुशों के चलते बुनियादी उद्योगों के उत्पादन में 7.6 प्रतिशत की गिरावट आई थी।

आर्थिक तरक्की पर

लौटा भारत: दास

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकवरी हो रही है, लेकिन दुनिया पर अभी भी कोविड का संकट बना हुआ है। अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए हर जरूरी कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरबीआई अप्रत्याशित, एकमुश्त नकदी प्रवाह का प्रबंधन करने के लिए परिचालन व्यवस्था को और दूरस्त करेगा। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे कोविड का खतरा कम होगा, हम बेहतरी के लिए कदम

एजेंसियों द्वारा जीडीपी को लेकर लगाए गए अनुमान	(%) में
एसबीआई	18.5
क्रिसिल	19.00
इक्रा	20.00
ईंडिया रेटिंग्स	15.30
डेलायट ईंडिया	17.7-21.8
आरबीआई	21.00
पीडब्ल्यूसी	20.00
वांटो रिसर्च	23

उठाते रहेंगे।

राजकोषीय घाटा लक्ष्य के 21.3 प्रतिशत पर पहुंचा

लेखा महानियंत्रक (सीजीए) द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई के अंत में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा 3.21 लाख करोड़ रुपये या बजट अनुमान का 21.3 प्रतिशत हो गया। हालांकि, यह पिछले वर्ष के मुकाबले काफी बेहतर है। कोरोना के चलते पिछले साल यह अनुमान के 103.1 प्रतिशत तक बढ़ गया था।

ऑल -न्यू रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 लीजेंड का हुआ पुर्नजन्म

इसके सफर की शुरुआत की। 12 साल और उसके बाद 3 मिलियन से ज्यादा मोटरसाइकल के साथ क्लासिक ने अपनी एक विरासत बना ली है और नई क्लासिक 350 इस विरासत को आगे ले जाने के लिए तैयार है।

क्लासिक की विरासत एवं ऑल - न्यू



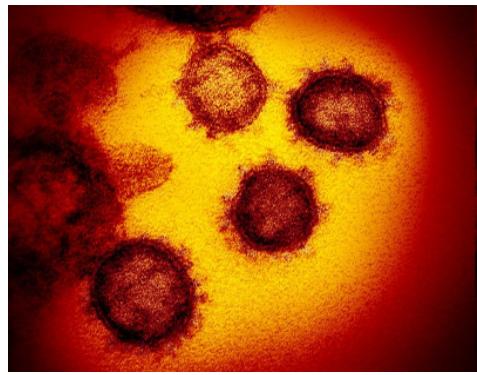
रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के लॉन्च के बारे में सिद्धार्थ लाल, मैनेजिंग डायरेक्टर, आयश शर्मा एवं टच प्लाईट्स को परफेक्शन दिया है। साथ ही इसकी राईड की परफॉर्मेंस अतुलनीय है। इसका उत्तम तरीके से कालिब्रेट किया गया इंजन बहुत स्मूथ है, समझदारी के साथ रेस्पॉन्स देता है एवं दिलचस्प है। यह एक्सेलरेशन के साथ शानदार ग्राउल प्रदान करता है। ऑल - न्यू चेसिस हैंडलिंग के बहुत अपार आत्मविश्वास प्रदान करता है और यह मोड

डब्ल्यूएचओ 'Mu' नाम के नए कोरोना वायरस संस्करण पर बनाए हुए हैं नजर

जनवरी में मिला था पहली बार
नई दिल्ली। एजेंसी

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि वह 'श्ल' नामक एक नए कोरोना वायरस संस्करण की निर्गती कर रहा है, जो पहली बार जनवरी में कोलंबिया में मिला था। श्ल, जिसे वैज्ञानिक रूप से B.1.621 के रूप में जाना जाता है, को 'वेरिएंट आफ इंटरेस्ट' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह जानकारी वैश्विक स्वास्थ्य निकाय ने अपने साप्ताहिक महामारी बुलेटिन में दी। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि वेरिएंट में ऐसे म्यूटेशन हैं जो कोरोना के खिलाफ टीका लगाने के बाद भी शरीर में अटैक कर सकता है और जोर देकर कहा कि इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए आगे के अध्ययन की आवश्यकता है। बुलेटिन में कहा गया है, 'श्ल' संस्करण कई म्यूटेशन का जोड़ है, जो वैक्सीन से बनी प्रतिरक्षा से बचने में कारगर हो सकता है। कहा गया कि नए वायरस म्यूटेशन के

उभरने से व्यापक विंता बनी है क्योंकि संक्रमण दर



फिर से विश्व स्तर पर बढ़ रहा है। यह अत्यधिक संक्रमक डेल्टा संस्करण के कारण बढ़ रहे हैं। विशेष रूप से असंक्रमित के बीच और उन क्षेत्रों में जहां एंटी-वायरस उपायों में ढील दी गई है।

SARS-CoV-2 सहित सभी वायरस, जो

सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता पहली तिमाही में 2,488 मेगावाट बढ़ी, तीन साल में सर्वाधिक: रिपोर्ट
नयी दिल्ली। एजेंसी

मेर्कॉम इंडिया रिसर्च के अनुसार अप्रैल-जून 2021 तिमाही के दौरान भारत की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 12 गुना बढ़कर 2,488 मेगावाट (मेगावाट) हो गयी। समीक्षाधीन तिमाही में क्षमता वृद्धि जनवरी-मार्च (पहली तिमाही) 2021 में स्थापित 2,090 मेगावाट की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक है। अनुसंधान कंपनी ने अपनी 'कार्टर्ट2 -2021 इंडिया सोलर मार्केट अपडेट' रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। इसमें कहा गया, 'भारत ने कैलेंडर वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही (अप्रैल-जून 2021) में 2,488 मेगावाट सौर क्षमता की वृद्धि की। यह सालाना आधार पर 2020 की दूसरी तिमाही के दौरान क्षेत्र कोविड-19 से प्रभावित हुआ था।' रिपोर्ट में कहा गया कि समीक्षाधीन अवधि में सौर उत्पादन क्षमता में वृद्धि 2018 की दूसरी तिमाही के बाद से किसी एक तिमाही में सर्वाधिक है। वहीं जनवरी-जून 2021 में देश में 4,578 मेगावाट (लगभग 4.5 गीगावाट) सौर क्षमता की वृद्धि हुई जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 251 प्रतिशत की वृद्धि है। यह क्षमता पूरे कैलेंडर वर्ष 2020 की 3.2 गीगावाट की स्थापित क्षमता से ज्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया कि कोविड-19 की वजह से कई राज्यों में लगाए गए लॉकडाउन के बावजूद पिछली तिमाही की तुलना में क्षमता में काफी ज्यादा वृद्धि दर्ज की गयी।

PayU ने किया Billdesk का 4.7 अरब डॉलर में अधिग्रहण

PROSUS का भारत में कुल निवेश बढ़कर हुआ 10 अरब डॉलर

नई दिल्ली। एजेंसी

वैश्विक उपभोक्ता इंटरनेट समूह और टेक्नोलॉजी निवेशक प्रॉसस एनवी ने मंगलवार को कहा कि उसकी डिजिटल भुगतान इकाई पेयू भारतीय डिजिटल भुगतान प्रदाता बिलडेस्क का 4.7 अरब डॉलर (करीब 34,376.2 करोड़ रुपये) में अधिग्रहण करेगी। प्रॉसस ने एक बयान में कहा कि पेयू और भारतीय डिजिटल भुगतान प्रदाता बिलडेस्क के शेरधारकों के बीच बिलडेस्क को 4.7 अरब डॉलर में खरीदने का समझौता हुआ है। बयान में कहा गया कि प्रस्तावित अधिग्रहण से प्रॉसस का भुगतान और फिनेटेक व्यवसाय पेयू विश्व स्तर पर अग्रणी ऑनलाइन भुगतान प्रदाताओं में शामिल हो जाएगा।

पेयू की 20 से अधिक उच्च वृद्धि वाले बाजारों में मौजूदी है और इसकी कुल भुगतान मात्रा (टीपीई) 147 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक होगी। बयान में कहा गया कि इस लेनदेन के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) से मंजूरी ली जानी है। बिलडेस्क की स्थापना 2000 में हुई थी। प्रॉसस के समूह सीईओ बॉब वैन डिजक ने कहा कि 2005 के बाद से भारत के कुछ सबसे गतिशील उद्यमियों और नए तकनीकी व्यवसायों के साथ हस्योग और भागीदारी के रूप में देश के साथ हमारा एक लंबा और गहरा संबंध है। हमने अब तक भारतीय

कोविड-19 से जुड़े हुए हैं, समय के साथ अपने को बदलने हैं और अधिकांश उत्परिवर्तन वायरस के गुणों पर बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। लेकिन कुछ म्यूटेशन वायरस के गुणों को प्रभावित कर सकते हैं और बता सकता है कि वह कितनी आसानी से फैलता है, इससे होने वाली बीमारी की गंभीरता बढ़ सकती है और टीकों का असर कम सहित कई समस्या हो सकती है। डब्ल्यूएचओ वर्तमान में ऐसे चार कोविड-19 वेरिएंट की पहचान कर चुका है, जो विंता का कारण हैं। इनमें अल्फा, जो 193 देशों में मौजूद है और डेल्टा, जो 170 देशों में मौजूद है। बताया गया कि श्ल समेत पांच वेरिएंट पर नजर रखी जानी है। कोलंबिया में पाए जाने के बाद श्ल को अन्य दक्षिण अमेरिकी देशों और यूरोप में पहचाना गया। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि अनुक्रमित मामलों में इसका वैश्विक प्रसार 0.1 फीसद से कम हो गया है। कोलंबिया में, हालांकि, यह 3.9 फीसद पर है।

News ये केन USE
सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा के दो कार्यकारी निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाया
नयी दिल्ली। एजेंसी

बैंक ऑफ बड़ौदा ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने उसके दो कार्यकारी निदेशकों विक्रमादित्य सिंह खिची और अजय के खुराना का कार्यकाल बढ़ा दिया है। बैंक ने एक नियामकीय सूचना में कहा कि सरकार ने खिची का कार्यकाल 30 सितंबर, 2021 से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख, 31 जुलाई, 2022 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने एक दूसरी नियामकीय सूचना में कहा कि खुराना का कार्यकाल 19 सितंबर, 2021 को समाप्त हो रहे उनके वर्तमान अधिसूचित कार्यकाल से आगे दो साल के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया गया है। पिछले हफ्ते सरकार ने कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को उनके कार्यकारी निदेशकों को दिए गए सेवा विस्तार के बारे में सूचित किया था। पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंध निदेशक (एमडी) तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को भी सेवा विस्तार दिया गया है।

महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स को भारतीय नौसेना का 1,349.95 करोड़ रुपये का ठेका
नयी दिल्ली। एजेंसी

महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने शुक्रवार को कहा कि समूह की कंपनी, महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स लिमिटेड (एमडीएस) को भारत सरकार की ओर से भारतीय नौसेना के आधुनिक युद्धपोतों के लिए इंट्रेग्रेटेड एंटी-सबमैरीन वारफेयर डिफेंस सूट (आईएडीएस) का अनुबंध प्राप्त हुआ है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक नियामकीय सूचना में कहा कि भारतीय कंपनियों से खुली निविदा के माध्यम से रक्षा मंत्रालय (एमओडी) द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली आमंत्रित की गई थी, जिसमें प्रणाली की क्षमता को साबित करने के लिए समुद्र में विस्तृत परीक्षणों के माध्यम से परखा गया था। महिंद्रा डिफेंस भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के लिए 14 आईएडीएस सिस्टम की आपूर्ति करेगी। घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए, महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स लिमिटेड के अध्यक्ष एसपी शुक्ला ने कहा, "यह पानी के नीचे पता लगाने और खतरों से सुरक्षा के लिए निझी क्षेत्र के साथ किया गया पहला बड़ा अनुबंध है। यह अनुबंध एक बार फिर आत्मानिर्भर भारत पहल की सफलता का प्रतीक है।" महिंद्रा डिफेंस ने कहा, "यह उन्नत प्रैयोगिकी प्रणाली भारतीय नौसेना के लिए किसी भारतीय कंपनी द्वारा विकसित की जा रही अपनी तरह की पहली प्रणाली है।" यह एक बहुमुखी प्रणाली है जो छोटे, मध्यम और बड़े सभी प्रकार के युद्धपोतों से संचालन में सक्षम है।

अरबों डॉलर के अमेरिकी हथियारों के जखीरे पर बैठा है तालिबान लड़ाकों ने भी पहन ली सलवार-कमीज की जगह वर्दी

काबुल। एजेंसी

तालिबान इस समय अरबों डॉलर के अमेरिकी हथियारों के जखीरे पर बैठा है। उसके लड़ाकों दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में शुमार अमेरिकी युद्धक हेलीकॉप्टरों के साथ फोटो खिचवाते और हमवीज जैसे वाहनों पर सवारी करते नजर आ रहे हैं। उनके कंधों पर अब अमेरिकी असाल्ट राइफल



हैं। यह वो साजोसामान है जो अमेरिका ने अफगानिस्तान की सेना मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर कोई तालिबानी पायलट बांधार हवाई अड्डे पर अमेरिका अफगान में 8.84 लाख हथियार और सैन्य उपकरण छोड़ आया है।

पर अमेरिका के ब्लैंक हॉक हेलीकॉप्टर को उड़ाने की कोशिश करता दिख रहा है। फोर्ब्स ने अमेरिकी रक्षा विभाग पेटागन के डिपार्टमेंट लॉजिस्टिक्स एजेंसी (डीएलए) के आंकड़ों के आधार पर दावा किया है कि अमेरिका अफगान में 8.84 लाख हथियार और सैन्य उपकरण छोड़ आया है।

तालिबान के हाथ किस तरह के हथियार लगे हैं:

- 8.84 ल

अजा एकादशी : व्रत का महत्व, मुहूर्त, कथा और पारण का समय जानिए

इस वर्ष 3 सितंबर 2021, शुक्रवार को भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी मनाई जा रही है। इस दिन भगवान् विष्णु का पूजन किया जाता है। व्रत का महत्व- हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। भाद्रपद मास की यह एकादशी अजा एकादशी के नाम से जनमानस में प्रचलित है। इस दिन व्रत का करने वालों को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर साफ-सुथरे वस्त्र धारण करके पूजा स्थल की साफ-सफाई करने के बाद ही श्री विष्णु और लक्ष्मी देवी का पूजन करना चाहिए। भाद्रपद कृष्ण पक्ष में आने वाली यह एकादशी समस्त पारों का नाश करने वाली

तथा अश्वमेध यज्ञ का फल देने वाली है। इस दिन विधि-विधान पूजन के पश्चात व्रत कथा पढ़नी अथवा सुनी चाहिए। निराहार व्रत रखकर शाम को फलाहार करके अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देने बाद ही स्वयं को भोजन करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने वाला व्यक्ति अंत में सभी सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को जाता है।

अजा एकादशी पूजन के मुहूर्त- अजा एकादशी तिथि का प्रारंभ-गुरुवार, 2 सितंबर 2021 को सुबह 06.21 मिनट से शुरू होगी और शुक्रवार, 3 सितंबर 2021 को सुबह 07.44 मिनट अजा एकादशी समाप्त होगी। अजा एकादशी का पारण शनिवार, 4



सितंबर 2021 को सुबह 05.30 मिनट से सुबह 08.23 मिनट तक रहेगा।

कथा- भाद्रपद कृष्ण एकादशी की कथा के अनुसार प्राचीनकाल में हरिशचंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा

राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा। मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने

मन में विचार करने लगता कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुःखभरी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि राजन तुम्हारे भाग्य से आज से सात दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी, तुम विधिपूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्धीन हो गए। राजा ने उनके कथनानुसार एकादशी आने पर विधिपूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। अंतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधिपूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है।



कुंडली में यदि ऐसी स्थिति हो तो ना पहनें सोना, वर्ना पछताएंगे

लाल किताब या ज्योतिष के अनुसार सोना किसे पहनना चाहिए और किसे नहीं इसका उल्लेख मिलता है। हालांकि यहां पर सोना कुंडली की स्थिति जानकर ही पहनेंगे तो फायदे में रहेंगे अन्यथा नुकसान होगा और आप पछताएंगे भी।

फायदा :

●गले में सोना पहने का अर्थ है कि आपका वृहस्पति ग्रह कुंडली के लग्न भाव में बैठ जाएगा या वहां का असर देगा। ●राथ में सोना पहनने का अर्थ है कि आपके पराक्रम अर्थात् तीसरे भाव में वृहस्पति सक्रिय भूमिका में रहेगा। ●यदि आपका लग्न मेष, कर्क, सिंह और धनु है तो आपके लिए सोना धारण करना उत्तम होगा।

नुकसान:

1. वृषभ, मिथुन, कन्या और कुंभ लग्न के लिए सोना धारण करना उत्तम नहीं होता है। 2. तुला और मकर लग्न के लोगों को सोना कम ही पहनना चाहिए। 3. वृश्चिक और मीन लग्न के लोगों के लिए सोना पहनना मध्यम है। 4. जिनकी कुंडली में वृहस्पति खराब हो या किसी भी प्रकार से दूषित हो ऐसे लोगों को भी सोने के प्रयोग से बचना चाहिए। 5. वृहस्पति की स्थिति जानकर ही सोना धारण करेंगे तो फायदा होगा अन्यथा नुकसान होगा।

महाभारत की सीखःकभी भी अपनी शक्तियों पर घमंड न करें और शत्रु को कमजोर न समझें

जन्माष्टमी के बाद अगले दिन नंद गांव में नंदोत्सव मनाया जाता है। नंद गांव मथुरा से कीरी 50 किमी दूर स्थित है। मायाता है कि जब नंद बाबा, यशोदा, कान्हा और बलदाऊ गोकुल में रहते थे, तब कंस बार-बार श्रीकृष्ण को मारने के लिए राक्षसों को भेज रहा था। गोकुल मथुरा से बहुत कीरी था। उस समय कान्हा की सुरक्षा के लिए नंद बाबा ने नंद गांव बसाया था। ये गांव मथुरा से कुछ दूरी पर है। इस गांव में आज भी जन्माष्टमी के बाद अगले दिन नंदोत्सव मनाया जाता है। इस दिन बाल गोपाल की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। श्रीकृष्ण भजन गाए जाते हैं।

श्रीकृष्ण ने अपने जीवन में अलग-अलग घटनाओं के माध्यम से कई ऐसे सूत्र बताए हैं, जिन्हें अपनाने से जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। जानिए श्रीकृष्ण और अर्जुन से जुड़ा एक ऐसा किस्सा, जिसमें श्रीकृष्ण ने घमंड से बचने की सलाह दी है।

महाभारत युद्ध में जब अर्जुन और कर्ण का आमना-सामना हुआ तो दोनों ही योद्धा पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। अर्जुन के बाण के कर्ण के रथ पर लगते तो उसका रथ 20-25 हाथ पीछे खिसक जाता था। जबकि कर्ण के प्रहरों

से अर्जुन का रथ 2-3 हाथ ही खिसकता था। जब-जब कर्ण का बाण रथ पर लगता श्रीकृष्ण उसकी प्रशंसा करते, लेकिन अर्जुन के बाणों के बारे में कुछ नहीं कह रहे थे। ये देखकर अर्जुन से रहा नहीं गया।

अर्जुन ने श्रीकृष्ण से पूछा, 'जब मैं बाण कर्ण के रथ पर लगते हैं तो उसका रथ बहुत पीछे खिसक जाता है, जबकि उसके बाणों से मेरा रथ थोड़ा सा ही पीछे खिसक रहा है तो उसके

बाण कमजोर नहीं हैं। तुम्हरे साथ मैं हूं और कर्ण के साथ सिर्फ उसका पराक्रम है। फिर भी वह तुम्हें कड़ी टक्कर दे रहा है। इसका मतलब यही है कि कर्ण तुमसे कमजोर नहीं है।' ये सुनकर अर्जुन का घमंड टूट गया। अर्जुन को समझ आ गया कि अपनी शक्तियों पर घमंड नहीं करना चाहिए और शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए।

इन 6 कारणों से दिखाई देते हैं हमें अच्छे या बुरे सपने

मनोविज्ञान, आयुर्वेद, ज्योतिष और योग में अच्छे या बुरे सपने दिखाई देने के कई कारण हैं। जब हम कोई स्वप्न देखते हैं तो जल्दी नहीं कि प्रत्येक सपने का अच्छा या बुरा फल होता है। आओ जानते हैं कि सपने किन कारणों से दिखाई देते हैं। अधिकतर सपने हमें हमारी दिनचर्या में किए गए कार्य से प्राप्त होते हैं। कार्य का अर्थ हमने जो देखा, सुना, समझा, इच्छा किया और भोगा वह हमारे चित्त में विराजित होकर रात में स्वप्नों के रूप में दिखाई देता है। यह सब बदले स्वरूप में इसलिए भी होते हैं क्योंकि वे हमारे शरीर में स्थित भोजन और पानी की स्थिति और अवस्था से भी संचालित होते हैं। निम्नलिखित बातों से आप समझ सकते हैं।

इन कारणों से दिखाई देते हैं स्वप्न :-

- वृष्ट- जो जाग्रत अवस्था में देखा गया हो उसे स्वप्न में देखना।
- श्रुत- सोने से पूर्व सुनी गई बातों को स्वप्न में देखना।
- अनुभूत- जो जागते हुए अनुभव किया हो उसे देखना।
- प्राथित- जाग्रत अवस्था में की गई प्रार्थना की इच्छा को स्वप्न में देखना।
- दोषजन्य- वात, पित्त आदि दूषित होने से स्वप्न देखना।
- भविक- जो भविक्ष में घटित होना है, उसे देखना।



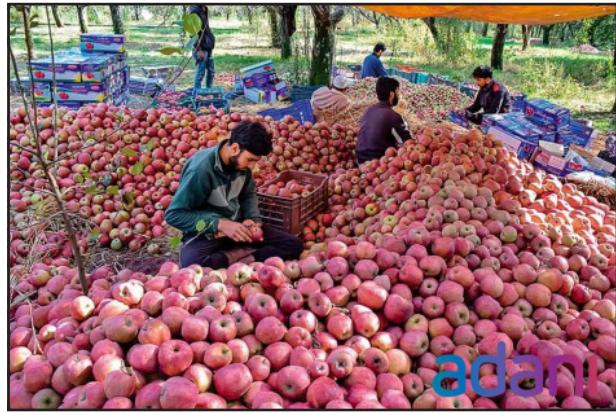
चाणक्य नीति: रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए इन बातों का रखना चाहिए ध्यान

जीवन में रिश्तों का खास महत्व होता है। अच्छे रिश्ते बुरे समय में साथ निभाते हैं। आचार्य चाणक्य ने बताया है कि व्यक्ति को अपने रिश्तों को हमेशा मजबूत रखना चाहिए। चाणक्य ने एक श्लोक में बताया है कि किन बातों का ध्यान रखने से रिश्ते मजबूत होते हैं।

1. प्रेम और विश्वास पर टिके होते हैं रिश्ते- किसी भी व्यक्ति के लिए हर व्यक्ति को खुश रख पाना मुश्किल होता

है। चाणक्य के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति छल-कपट का सहारा लेता है तो, उसके रिश्ते ज्यादा समय तक टिके नहीं रहते हैं। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए।

अदाणी एग्री फ्रेश ने किसानों से 2,500 टन सेब खरीदा



नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

अदाणी एग्री फ्रेश ने इस साल खरीद (प्रोक्योस्मेंट) सीजन के पहले तीन दिनों के भीतर ही

किसानों से लगभग 2,500 टन सेब खरीदा है। किसानों की ओर से कंपनी को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, क्योंकि अदाणी एग्री फ्रेश ने मंडियों की तुलना में अधिक

कीमतों का ऑफर दिया था। अदाणी एग्री फ्रेश शिमला जिले में 'कंट्रोल एटमार्स्फी यार फैसिलिटीज' के जरिये सेब खरीदती है और 'फार्म-पिक' ब्रांड नाम से इसका प्रसार करती है। सेब खरीद सीजन पिछले सप्ताह शुरू हुआ था और यह अक्टूबर के अंत तक जारी रहेगा।

हिमाचल प्रदेश में अदाणी एग्री फ्रेश के अधिकारी ने बताया कि खरीद सीजन के पहले ही दिन उन्हें लगभग 1,000 टन सेब प्राप्त हुए, जबकि पिछले वर्षों के दौरान लगभग 300 टन सेब ही मिले थे। अधिकारी ने अपना नाम न छापने का अनुरोध करते

हुए कहा कि 'अदाणी एग्री फ्रेश सेब की खरीद प्रति किलोग्राम के आधार पर करता है, जबकि उसे मंडियों में प्रति बॉक्स बेचना पड़ता है। बॉक्स के आकार के बजाय सेब के हर ग्राम के लिए रिटर्न पाकर किसान खुश हैं।'

लेकिन जब कुछ मीडिया हाउस ने रिपोर्ट दी कि अदाणी एग्री फ्रेश ने इस सीजन में सेब की खरीद कीमतों को संशोधित कर दिया है तो अदाणी एग्री फ्रेश राजनेताओं के एक वर्ग के निशाने पर आ गया। कंपनी के अधिकारी ने दावा किया कि मंडियों अपनी सेब खरीद कीमतों को बढ़ाने के लिए मजबूर हैं क्योंकि कंपनी के अपनी उपज बेचना चाहते हैं। हालांकि, उन्होंने अदाणी एग्री

फ्रेश को आपूर्ति करना जारी रखा है जो सेब की कीमतें गिरने के बावजूद, मंडियों की तुलना में अधिक कीमतें दे रहे हैं। अदाणी एग्री फ्रेश ने लगभग

15 वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश में सेब के व्यापार में प्रवेश किया था और आज यह शिमला, किशौर और कुल्लू घाटियों के 700 गांवों में फैले 17,000 से अधिक किसानों से सौदे करती है। कंपनी अपनी फील्ड टीम के जरिये किसान को फसल कटाई से पहले और बाद में परामर्श सुविधा मुहैया कराती है, ताकि उन्नत गुणवत्ता के साथ उत्पादन बढ़ाया जा सके।

टेस्ला को चार मॉडल बनाने या इंपोर्ट करने की इजाजत मिल सकता है आयात शुल्क में आंशिक कटौती का लाभ

नई दिल्ली। एजेंसी

आप जल्द ही टेस्ला की गाड़ियों को सड़कों पर दौड़ा देख पाएंगे। कंपनी को इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार मॉडल देश में ही बनाने या उनको इंपोर्ट करने की इजाजत मिली है। उनको यहां की सड़कों पर चलने लायक होने का सर्टिफिकेट मिल गया है। इससे जुड़ी जानकारी केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद है।

कस्टम्स ड्यूटी में आंशिक कटौती की राहत

खबर यह भी है कि सरकार टेस्ला को कस्टम्स ड्यूटी में आंशिक कटौती की राहत दे सकती है। सूत्रों ने बताया कि इसके लिए उसने कंपनी से भारत में निवेश की योजना का व्योरा मांगा गया है। उन्होंने बताया कि संबंधित मंत्रालय कंपनी की मांग पर विचार कर रहे हैं और अंतिम फैसला कंपनी का प्लान मिलने के बाद ले लेंगे।

यहां की सड़कों के लायक होने का सर्टिफिकेट

सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक, 'टेस्ट से पक्का हो गया है कि टेस्ला की गाड़ियां भारतीय बाजार के हिसाब से सही हैं। ये एमिशन और सेप्टी नार्स पर खरी उतरी हैं। यहां की सड़क पर चलने लायक स्थिति में भी हैं।' एक टेस्ला फैन

इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सरकार का OK

टेस्ला की गाड़ियों की टेस्टिंग, एमिशन और सेप्टी नार्स पर खरी उतरी है। अमेरिका में मॉडल Y की कीमत 54000 डॉलर, 40000 डॉलर की है मॉडल 3

क्लब ने हाल में इस बाबत ट्वीट किया था। उसने कहा था कि भारत में मॉडल 3 और मॉडल 4 के वैरिएंट आ सकते हैं।

सबसे सस्ती गाड़ी मॉडल 3 की कीमत अमेरिका में 40,000 डॉलर

टेस्ला की सबसे सस्ती गाड़ी मॉडल 3 की कीमत अमेरिका में 40,000 डॉलर है। एक बार चार्ज करने पर 263 किलोमीटर तक जा सकती है। इसमें पांच लोगों के बैठने की जगह है। टॉप स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। 5.3 सेकंड में 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। मॉडल 4 सात सीट वाली गाड़ी है। इसकी कीमत अमेरिका में 54,000 डॉलर है। यह एक बार चार्ज होने पर 326 किलोमीटर तक जा सकती है। इसकी टॉप स्पीड 135 किलोमीटर प्रति घंटा है। 4.8 सेकंड में 60 मील प्रति घंटे की स्पीड में आ सकती है।

आसान नहीं भारत का बाजार

हालांकि, टेस्ला के लिए भारतीय कार बाजार में पकड़ बनाना आसान नहीं होगा। इसकी कई वजहें हैं- पहली, यहां हर साल जितनी गाड़ियां बिकती हैं, उनमें सिर्फ एक पर्सेंट ही इलेक्ट्रिक होती हैं। दूसरी, टेस्ला की इलेक्ट्रिक गाड़ियां बहुत महंगी होती हैं। तीसरी, यहां चार्जिंग फैसिलिटी कम है। चौथी, यहां इंपोर्टेंड गाड़ियों पर हेवी टैक्स लगता है।

इंपोर्ट गाड़ियों से टेस्टिंग, कामयाबी मिलने पर फैक्टरी लगाएगी

टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने पिछले महीने ट्रीट किया था कि इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी काफी ज्यादा है। ट्रैक्स के लिहाज से यहां इलेक्ट्रिक गाड़ियों को डीजल और पेट्रोल गाड़ियों के बराबर माना जाता है। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर उन्हें इंपोर्ट गाड़ियों से कारोबार जमाने में कामयाबी मिलती है, तो यहां फैक्टरी भी लगा सकते हैं।

टेस्ला चाहती है कि लक्जरी नहीं ही एंट्री माना जाए गाड़ियों को

टेस्ला पूरी तरह से असेंबल गाड़ियों पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर 40% करने की मांग कर रही है। यहां 40,000 डॉलर से सस्ती गाड़ियों पर 60% और उससे महंगी गाड़ियों पर 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। कंपनी चाहती है कि उसकी गाड़ियों को लक्जरी नहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल माना जाए।

हीरो इलेक्ट्रिक ने ग्रामीण भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की बिक्री बढ़ाने के लिये भागीदारी की

पुणे। आईपीटी नेटवर्क

भारत की सबसे बड़ी ईवी टू-व्हीलर कंपनी हीरो इलेक्ट्रिक ने व्हीकल्स ईएमआई प्राइवेट लिमिटेड के साथ अपने गठबंधन की घोषणा की है। यह गठबंधन भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स खरीदने के लिये फाइनेंसिंग के आसान विकल्प प्रदान करने के लिये किया गया है। हीरो इलेक्ट्रिक अभी हर महीने 10,000 से ज्यादा टू-व्हीलर्स की बिक्री कर रहा है और इसमें से 40% बिक्री भारत के ग्रामीण इलाकों में हो रही है। कंपनी को उम्मीद है कि इस भागीदारी से बिक्री बढ़ेगी और वर्ष 2021 के अंत तक यह पिछले साल की तुलना में दोगुनी हो सकती है।

ईंधन के बढ़ते दामों और FAME-2 सब्सिडीज में बदलाव के चलते ऐसे ग्राहकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, जो ईवी टू-व्हीलर का विकल्प अपनाकर ग्रीन रिवॉल्यू शन का हिस्सा बनाना चाहते हैं। उपभोक्ताओं के लिये इसे आसान बनाने और खरीदारी का तुरंत फैसला लेने में उनकी मदद करने के लिये अब फाइनेंस विकल्पों की एक व्यापक श्रृंखला आ गई है। इनकी मदद से उपभोक्ताद अब एक ब्राण्ड न्यू हीरो ईवी खरीदकर इलेक्ट्रिक होने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। यह गठबंधन हीरो इलेक्ट्रिक के ग्राहकों को अतिरिक्त फायदे भी देता है।

हीरो इलेक्ट्रिक की इस नई टू-व्हीलर रिटेल फाइनेंस भागीदारी के बारे में हीरो इलेक्ट्रिक के सीईओ श्री सोहिंदर गिल ने कहा, "पिछले कुछ हफ्तों में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर जागरूकता और मांग अपने चरम पर रही है। इसके कारण विभिन्न हो सकते हैं, संशोधित FAME-2 और राज्यों की नीतियों से लेकर ईंधन के दामों में बढ़त तक।

रेनमेकर का दुनिया का पहला क्रिप्टो करेंसी फैटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

पिछले साल, स्वीकृति के आधार पर भारत

दुनिया के दूसरे सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी मार्केट के रूप में उभरा। पूरे अनुभव में क्रांति लाने के उद्देश्य से, भारत के क्रिप्टो उत्पादी और क्रिप्टो जिजासुओं को एक नया और अनूठा ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करने के लिए, रेनमेकर द्वारा दुनिया का पहला क्रिप्टोकरेंसी फैटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म आज लॉन्च किया गया। रेनमेकर, इन्वेस्टमेंट एवेन्यू की बारीकियों को मजेदार तरीके से सीखने में सुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए समझ को आसान बनाने के मूल दृष्टिकोण पर आधारित है। यह, खिलाड़ियों को आमत्रित करके, क्रिप्टो पोर्टफोलियो

डी बीयर्स फॉरएवरमार्क ने अपने 10वें वार्षिक इंडिया फोरम का आयोजन किया



मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

डी बीयर्स फॉरएवरमार्क ने 24 से 26 अगस्त, 2021 के दौरान मुंबई में अपने 10वें वार्षिक फोरम का आयोजन किया। डायमंड ब्रांड

द्वारा हाइब्रिड इवेंट का आयोजन किया गया जिसमें व्यक्तिगत एवं वर्चुअल दोनों तरीकों से लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया, और इसके बाद ब्रांड के भागीदारों, हीरा

कारोबारियों, आभूषण निर्माताओं, और संरक्षकों की कुल संख्या 8 लाख तक पहुंच गई। इस साल का फोरम 'मेक लाइफ ब्रिलियंट' की थीम पर आधारित है, जो डी बीयर्स के संकल्प और विश्वास को दर्शाती है कि इसके हीरे अपने ग्राहकों, समुदायों और पूरी धरती के जीवन को शानदार बनाने की ताकत रखते हैं। यह बात वर्ष 2030 तक संवहनीयता के लक्ष्य को हासिल करने के इसके साहसिक और महत्वाकांक्षी निर्णय के साथ-साथ हमेशा कायम रहने वाले आभूषणों के निर्माण तथा इसके कभी पुराने नहीं होने वाले डिजाइनों से भी झ़लकती है। इस तीन दिवसीय समारोह के दौरान, डी बीयर्स की ओर से कई रोमांचक और बेहद महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं, जिसमें

फॉरएवरमार्क का नाम बदलकर डी बीयर्स फॉरएवरमार्क करने की घोषणा भी शामिल है। ब्रांड के नाम में यह बदलाव, वास्तव में डी बीयर्स ब्रांड में बड़े पैमाने पर होने वाले परिवर्तन का हिस्सा है, जो समाज एवं पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए तथा जिम्मेदारी के साथ की गई सोसाइटी के फायदों को ग्राहकों तक पहुंचाने पर केंद्रित है, जिसका फायदा कंपनी द्वारा उन स्थानों और वहाँ के लोगों को दिया जाता है जहां वह हीरे की खोज करती है। इस तरह फॉरएवरमार्क और प्रतिष्ठित डी बीयर्स ब्रांड, डी बीयर्स ग्रुप के संवहनीयता को स्थायी बनाने के संकल्प तथा डायमंड के क्षेत्र में कंपनी की 130 से अधिक सालों की विशेषज्ञता के बीच घनिष्ठ संबंध का निर्माण होगा। डी बीयर्स

साल का यह फोरम हमारे लिए एक बेहतरीन मौका है, जहां हमने नए तौर-तरीके के साथ तालमेल बिठाते हुए वर्चुअल और फिजिकल, दोनों माध्यमों को अपनाया है। हमारे लिए यह फोरम अपने पार्टनर्स को एकजुट करने, चिचारों का आदान-प्रदान करने और तीन दिनों तक संचालन करने का एक अवसर है, और इस दौरान हमने कई नई एवं रोमांचक घोषणाएं की हैं, जिनमें ब्रांड को डी बीयर्स फॉरएवरमार्क के रूप में प्रस्तुत करना, फॉरएवरमार्क अवन्ति कलेक्शन का लॉन्च और हमारे नए कोड ऑफ ऑरिजिन प्रोग्राम के साथ-साथ नेशनल ज्योग्राफिक के साथ हमारी नई साझेदारी शामिल है, और यह साझेदारी वाकई उत्साह बढ़ाने वाली है।

भारतीय विमानन उद्योग को 26,000 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान: रिपोर्ट

मुंबई। एजेंसी

महामारी के झटके से भारतीय विमानन उद्योग को चालू वित वर्ष 2021-22 में 25,000 से 26,000 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हो सकता है। वहीं मौजूदा वित वर्ष में उद्योग का ऋण बढ़कर 1.2 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच सकता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इक्रा ने मंगलवार को यह अनुमान लगाया है।

इक्रा ने कहा कि इसके अलावा उद्योग को चालू वित वर्ष से 2023-24 तक 45,000-47,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तोषण की जरूरत होगी।

रेटिंग एजेंसी ने कहा कि निकट भविष्य में भारतीय एयरलाइंस का बही-खाता दबाव में रहेगा। उन्हें इस दबाव को कम करने के लिए

अपने कर्ज के बोझ को कम करना होगा। एयरलाइंस अपने परिचालन प्रदर्शन में सुधार या इक्विटी निवेश के जरिये ऐसा कर सकती है। इक्रा ने भारतीय विमानन उद्योग के लिए

हवाई यात्रियों के मामले में सालाना आधार पर 45 से 50 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज करेगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के मामले में यह वृद्धि 80 से 85 प्रतिशत

रहेगी। इक्रा ने कहा कि यह वृद्धि पिछले साल के निचले आधार प्रभाव तथा टीकाकरण की रफ्तार तेज होने तथा अंकुशों में ढील से हासिल होगी।

रिपोर्ट में कहा गया है, "हालांकि, यह वृद्धि 2015-16 और 2012-13 के स्तर से कम रहेगी।" इक्रा की उपाध्यक्ष एवं सह-समूह प्रमुख किंजल शाह ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर की वजह से यात्रियों की संख्या में सुधार काफी धीमा है। घरेलू यात्रियों का अंकड़ा 2023-24 तक ही महामारी-पूर्व के स्तर पर पहुंच पाएगा।



नकारात्मक साख परिवृत्त्य को कायम रखा है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि ज्यादातर एयरलाइंस ने मांग प्रभावित होने तथा जेट इंडियन की कीमतों में वृद्धि की वजह से पैदा हुए नकदी संकट से निपटने के लिए धन जुटाने की योजना बनाई है।

इक्रा का मानना है कि 2021-22 के दौरान विमानन उद्योग घरेलू

को निपटने के लिए खर्च में हुई बढ़ोतारी के चलते हुआ। वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटा यानी सरकार की

आय और खर्च के बीच का अंतर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 9.3 प्रतिशत रहा। यह अंकड़ा फरवरी के बजट में दर्शाये गये 9.5 प्रतिशत के संशोधित अनुमान से बेहतर रहा। अंकड़ों के अनुसार जुलाई

2021 तक केंद्र सरकार की

में कुल प्राप्तियां 2019-20 के बजट अनुमानों के

मुकाबले 10.4 प्रतिशत थीं। जुलाई 2021 तक कुल प्राप्तियों में 5,29,189 करोड़ रुपये कर राजस्व (केंद्र को शुद्ध प्राप्ति), 1,39,960 करोड़ रुपये गैर- कर राजस्व और 14,148 करोड़ रुपये गैर- रिण पूंजी प्राप्तियों में 5,777 करोड़ रुपये कर्ज की वसूली और 9,371 करोड़ रुपये विनिवेश प्राप्तियां शामिल हैं।

इस तरह सरकार का कुल व्यय 10.04 लाख करोड़ रुपये या 2021-22 के बजट अनुमानों का 28.8 प्रतिशत था। यह अंकड़ा एक साल पहले की समान अवधि में 2019-20 के बजट अनुमानों के मुकाबले 34.7 प्रतिशत था।



ओडिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पहले शोरूम का शुभारंभ

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

इस नए आउटलेट के शुभारंभ से देशभर में ओडिसी डीलरशिप की कुल संख्या अब 31 हो गई है, साथ ही आने वाले कुछ महीनों के दौरान कई और आउटलेट्स के संचालन की शुरुआत की जाएगी।

इस नई फैसिलिटी के उद्घाटन पर अपने विचार व्यक्त करते हुए श्रीमित महेता, सेल्स हेड, ओडिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने कहा, 'राज्य में ओडिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुसरी डीलरशिप के शुभारंभ पर

हमें गर्व का अनुभव हो रहा है। उन्होंने बताया इस नए डीलरशिप के लॉन्च के साथ हमने मध्य प्रदेश में हमारे नेटवर्क को मजबूत बनाने की दिशा में एक और कदम उठाया है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक स्कूटर की मांग में लगातार वृद्धि नजर आई है जो बेहद उत्साहजनक है।

ई-बाइक्स एवं स्कूटर के अलावा, शोरूम में मर्डेडाइज और एक्सेसरीज जैसे हेलमेट, स्कूटर के लिए प्लस गार्ड, जैसे वाहन से संबंधित वस्तुएं एवं सहायक उपकरण भी उपलब्ध हैं। आने वाले दिनों में पूरे भारत में चरणबद्ध तरीके से और भी कई एक्सेसरीज को भी उपलब्ध कराया जाएगा। इंदौर के फ्यूमोटिव प्राइवेट लिमिटेड एमटी सुधांशु शर्मा ने बताया कि ओडिसी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए अलग बहाव रखते हैं।

इन वाहनों में स्पोर्टी लुक वाली बाइक को खासा पंसद किया गया है। इस बाइक में सारंड लुक के बाजार में तेजी से बढ़ावा मिल रहा है।

केंद्र का राजकोषीय घाटा जुलाई अंत में वार्षिक लक्ष्य का 21.3 प्रतिशत

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

महालेखा नियंत्रक (सीजीए) द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई अंत में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा 3.21 लाख करोड़ रुपये या पूरे साल के बजट अनुमान का 21.3 प्रतिशत रहा। चालू वित वर्ष में राजकोषीय घाटे के अंकड़े पिछले वित वर्ष की तुलना में काफी बेहतर लग रहे हैं। पिछले वित वर्ष में इस अवधि में यह वार्षिक अनुमान के मुकाबले 103.1 प्रतिशत तक बढ़ गया था। ऐसा खासतौर से कोविड-19 महामारी से

निपटने के लिए खर्च में हुई बढ़ोतारी के चलते हुआ। वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटा यानी सरकार की आय और खर्च के बीच का अंतर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 9.3 प्रतिशत रहा। यह अंकड़ा फरवरी के बजट में दर्शाये गये 9.5 प्रतिशत के संशोधित अनुमान से बेहतर रहा। अंकड़ों के अनुसार जुलाई 2021 तक केंद्र सरकार की कुल प्राप्तियां 6.83 लाख करोड़ रुपये या बजट अनुमानों का 34.6 प्रतिशत थीं। बीते वित वर्ष की समान अवधि

